

पुपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▶ Issue : 26 ▶ Mumbai ▶ Friday, 31 July to 06 August 2026 ▶ Weekly ▶ Pages : 8 ▶ Price : 3 Rs.

प्रकृति, पर्यावरण और समस्त सृष्टि का सम्मान हमारे अस्तित्व के मूल में है : पीएम मोदी



नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए देशवासियों को भारतीय संस्कृति के गूढ़ दर्शन, पर्यावरण संरक्षण और सनातन परंपराओं से जुड़ने का एक खास संदेश दिया है। संस्कृत श्लोकों (सुभाषित) और उनके मर्मस्पर्शी हिंदी अर्थों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने प्रकृति के प्रति सेवाभाव और

कृतज्ञता व्यक्त करने की बात कही। उन्होंने लिखा, 'प्रकृति, पर्यावरण और समस्त सृष्टि का सम्मान हमारे अस्तित्व के मूल में है। आइए, हम इनके प्रति पूरी कृतज्ञता और सेवाभाव के साथ एक स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनें।' इससे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने गुरु-शिष्य परंपरा को नमन करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि

शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सुभाषित शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा गया था, 'प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में ही मानवता का कल्याण निहित है। हमारी परंपरा भी हमें इसी धर्मसम्मत आचरण की प्रेरणा देती है।' उन्होंने संस्कृत श्लोक, 'लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा। ऋतवः षट् च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥ दिनानि

च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः ॥' भी साझा किया था। जिसका हिंदी अर्थ है कि प्रकृति और धर्म के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ही सुख, सुरक्षा और मंगल का आधार है। अतः दिशाओं के रक्षक देवता, इंद्र आदि प्रमुख देवगण, छह ऋतुएं, सभी मास, वर्ष, रात्रियां, दिन और शुभ मुहूर्त सदैव कल्याणकारी हों। वेद, स्मृतियां और धर्म भी सभी प्रकार से सर्वत्र सबकी रक्षा करें।

दुश्मन पनडुब्बियों की अब खैर नहीं

नौसेना का अत्याधुनिक पोत 'मछलीपटनम' लॉन्च

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में निर्मित माहे श्रेणी के सातवें उथले जल में चलने वाले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत (एसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) 'मछलीपटनम' का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव वाइस एडमिरल अतुल आनंद की उपस्थिति में श्रीमती गुलरुख आनंद ने जहाज का औपचारिक शुभारंभ किया। समारोह में भारतीय नौसेना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। 'मछलीपटनम' का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपटनम के नाम पर रखा गया है। यह शहर भारत के पूर्वी तट पर अपनी समृद्ध समुद्री विरासत और ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह युद्धपोत उसी गौरवशाली विरासत का प्रतीक होने के साथ भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मछलीपटनम को समुद्र के भीतर निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियान (एसडब्ल्यू), निम्न तीव्रता वाले समुद्री



अभियान (एलआईएमओ) और बारूदी सुरंगों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के लिए तैयार किया गया है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा समुद्री क्षेत्र में निगरानी और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। मछलीपटनम का शुभारंभ एसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी परियोजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह परियोजना रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने का भी प्रतीक है। इस परियोजना में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

(शेष पेज 5 पर)

रक्षा मंत्री ने 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान को पूरा करने पर

आईएससी त्रिवेणी की महिला क्रू टीम को किया सम्मानित

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने पर भारतीय ऑटोनॉमस सरफेस वेसल (आईएससी) त्रिवेणी की तीनों सेनाओं की महिला क्रू टीम को सम्मानित किया। नई दिल्ली में महिला अधिकारियों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने चार महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की 314 दिनों की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में टीम के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने इस अभियान को 'नारी शक्ति' का प्रमाण और त्रि-सेवाओं के आपसी सहयोग व तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। महिला अधिकारियों ने राजनाथ सिंह के साथ अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि इस मुश्किल अभियान ने उनकी यात्रा को यादगार बनाया। उन्होंने कहा कि देश को गौरवान्वित करने के मजबूत इरादों ने उन्हें प्रेरित रखा, जिससे वे भारी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना कर सकीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि महिला टीम के समर्पण ने उन्हें प्रेरित किया और उनके अपने संकल्प को और मजबूत किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि महिला टीम की उपलब्धि यह दिखाती है कि मजबूत विश्वास और दृढ़ संकल्प से



जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अफसरों की काबिलियत और आत्मविश्वास को 'अविश्वसनीय' बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 'समुद्र प्रदक्षिणा' की कामयाबी ने उन रूढ़िवादी सोच को तोड़ दिया है जिनके अनुसार महिलाएं मुश्किल सैन्य मिशन पूरे नहीं कर सकतीं। उन्होंने महिला अफसरों से कहा, "आपने साबित कर दिया है कि शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व के गुण जेंडर तक सीमित नहीं हैं। भारत की हर बेटी आपको देखकर यह विश्वास कर सकती है कि वह भी समुद्र पार कर सकती है और दुनिया जीत सकती है।" रक्षा मंत्री ने इस अभियान को 'तीनों सेनाओं के संयुक्त सहयोग' का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और

भारतीय वायु सेना की महिला अफसरों ने एक साझा मिशन के लिए एक ही झंडे के नीचे और एक ही जहाज पर साथ मिलकर यात्रा की। उन्होंने आगे कहा, "यह अभियान इस बात का सबूत है कि अगर हम मिलकर आगे बढ़ें, तो कोई भी मंजिल इतनी बड़ी नहीं है जिसे हासिल न किया जा सके।" वहीं, राजनाथ सिंह ने कहा, "मैं महसूस कर सकता हूँ कि 'आईएससी त्रिवेणी' के साथ जब आप दूसरे देश में जाते होंगे, तो वहां पर किस तरह से आप भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, स्वदेशी क्षमता और तकनीकी विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। आपने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी उपस्थिति से पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।"

(शेष पेज 5 पर)

भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की

नई दिल्ली: भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं, एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। 38 वर्षीय रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में भारत के लिए कुल 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर वर्ष 2013 में शुरू हुआ था।



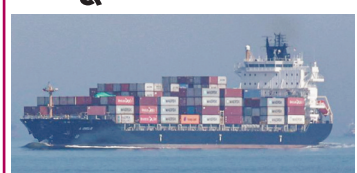
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि



नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से उत्पन्न अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं।

(शेष पेज 5 पर)

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया



नई दिल्ली: भारत दुनिया में नाविकों के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक शिपिंग उद्योग में 311,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। बीआईएमसीओ-आईसीएस नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत अब वैश्विक समुद्री कार्यबल का 12.16 प्रतिशत हिस्सा है, जो केवल फिलीपींस से पीछे है और चीन, रूसी संघ और इंडोनेशिया से आगे है। (शेष पेज 5 पर)

जिला प्रशासन और बीएसएफ ने जारी किए सख्त आदेश

राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट घूमने पर रोक

जयपुर: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में शाम छह से सुबह सात बजे तक बिना अनुमति घूमने पर रोक लगाई गई है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शाम सात से सुबह छह बजे तक किसी भी व्यक्ति के घूमने पर रोक लगाई गई है। श्रीगंगानगर जिले में सीमा के निकट खेतों में काम करने अथवा सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के आने-जाने और ठहरने के लिए अनुमति लेना आवश्यक किया गया है।



संपादकीय

धरती की चेतावनी को सुनिए

प्रकृति का धैर्य अब जवाब दे रहा है

पूरी दुनिया में मौसम के तेजी से बिगड़ते मिजाज के कारण विभिन्न देशों में प्रकृति की मार अब स्पष्ट नजर आने लगी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही परिणाम है कि अब हर साल देश के कई हिस्से भारी बारिश के कारण बाढ़ की वजह से त्राहि-त्राहि करते नजर आते हैं जबकि कई हिस्से मानसून के दौरान भी पर्याप्त बारिश के लिए तरसते रह जाते हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दुनिया के कई ठंडे इलाके अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण तपने लगे हैं तो कई सूखे इलाके बाढ़ से त्रस्त हैं, जंगल झुलस रहे हैं। बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विश्वभर में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के चलते प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिहाज से आज के समय में प्रकृति संरक्षण दिवस की महत्ता बढ़ गई है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौर में पूरी दुनिया ने पहली बार प्रकृति को खुलकर मुस्कराते देखा था क्योंकि तब औद्योगिक इकाईयां, हवाई व रेल यात्राएं, बस यात्रा तथा निजी वाहनों का आवागमन बंद होने से हर तरह के प्रदूषण का स्तर पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया था। गंगा, यमुना जैसी जो पवित्र नदियां कई जगहों पर गंदे नालों की भांति बहती दिखाई देती थी, उनमें जल की निर्मल धारा बहने लगी थी। जिन नदियों को साफ करने के लिए पिछले कुछ दशकों में अनेक योजनाएं और समितियां बनी तथा नदियों की स्वच्छता के नाम पर अरबों-खरबों रुपये खर्च हो गए, लॉकडाउन के दौरान वे स्वतः ही स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। पहली बार देखा गया था कि किस प्रकार लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों में बंद रहने और सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्य बंद हो जाने से हवा इतनी शुद्ध हो गई थी कि सैंकड़ों किलोमीटर दूर स्थित पर्वतों की चोटियां भी स्पष्ट दिखाई दी थी। दरअसल प्रकृति को स्वयं अपनी मरम्मत करने और खुद को सजाने-संवारने का सुअवसर मिला था लेकिन इंसानी गतिविधियां पुनः शुरू होते ही प्रकृति के साथ निर्मम खिलवाड़ का वही दौर पुनः शुरू हो गया, जिसका परिणाम इस समय दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। हालांकि प्रकृति बार-बार अपना रौद्र रूप दिखाकर स्पष्ट चेतावनी देती रही है कि यदि उसके साथ अंधाधुंध खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो उसके घातक परिणाम होंगे लेकिन विडम्बना है कि लगातार प्रकृति का प्रचण्ड रूप देखते रहने के बावजूद प्रकृति की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दुनिया अपने विनाश को आमंत्रित कर रही है। दरअसल हम समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों का सीना चीरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम कंक्रीट के जो जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं है बल्कि विकास के नाम पर हम अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रकृति कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकम्प, कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें बारम्बार चेतावनी देती रही है कि हम यदि इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का बुरे तरीके से दोहन करते रहे तो हमारे भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है। यदि हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति से साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

परीक्षा के साथ शिक्षा में भी हो सुधार

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट में एक लाख से अधिक स्थानों के लिए 22 लाख से अधिक छात्र बैठते हैं। यह चीनी यूनिवर्सिटियों में प्रवेश दिलाने वाली गाओकाओ परीक्षा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है। पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से छात्रों की मेहनत और लाखों की कोचिंग पर पानी फिर जाता है। नीट जैसी लीक गाओकाओ में नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर सेट करने वालों का संपर्क काटकर उन्हें परीक्षा शुरू होने तक गुप्त स्थानों पर रखा जाता है और पेपर कड़ी सुरक्षा के साथ सेना की गाड़ियों में परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाते हैं। हालांकि भारत में भी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं से लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के बिना संपन्न होती हैं, परंतु नीट में इसकी शुरुआत से ही गड़बड़ियां होती रही हैं। सीबीएसई और नीट जैसी परीक्षाओं में तो पेपर लीक के अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी गड़बड़ी के मामले सामने आए। गड़बड़ियां केन्द्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं में ही नहीं, बल्कि राज्य एजेंसियों की परीक्षाओं में भी हो रही हैं। इसलिए प्रवेश और भर्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सीमित होते स्थान और फैलते कदाचार को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जो परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल कर सके। प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि पेपर सेट करने वाले सुयोग्य और सत्यनिष्ठा संपन्न हों। कोचिंग उद्योग के साथ उनका कोई संबंध न हो। पेपर सेट होने के बाद से परीक्षा होने तक वे कड़ी निगरानी में रहें और पेपर बनने से लेकर वितरण तक का काम संघ लोक सेवा आयोग जैसी किसी विश्वसनीय एजेंसी के हाथों में रहे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की परख करने की जगह अब उनकी समाधान



बुद्धि और मौलिक विचारशक्ति को अधिक परखने की जरूरत है। इससे एक तो इन परीक्षाओं पर कोचिंग उद्योग का शिकंजा ढीला पड़ेगा। दूसरे चयन ऐसे प्रत्याशियों का होगा, जो एआइ के तेज विकास के कारण रोजगारों के बदलते स्वरूप के साथ भी बड़ी आसानी से सामंजस्य बिठा सकेंगे। नए कौशल सीखने में तत्पर, समाधान बुद्धि रखने वाले, समीक्षात्मक चिंतन और रचनात्मक स्वभाव वाले लोगों की मांग बढ़ेगी। भारत में हर साल लगभग एक करोड़ छात्र स्नातक बनते हैं, जिनमें 17 लाख से अधिक इंजीनियर, एमबीए और डाक्टर होते हैं। हालांकि व्यावसायिक और औद्योगिक कौशल नहीं होने के कारण चार में से केवल एक एमबीए, पांच में से एक इंजीनियर और हर दस में से एक स्नातक ही काम पर लगाने लायक होता है। यह ऐसा टाइम बम है, जो भारत का वरदान समझी जाने वाली युवा शक्ति को अभिशाप में बदल सकता है। इसे अभिशाप में बदलने से रोकने के लिए शिक्षा प्रणाली में उद्योगों और कारोबारों की मांग के हिसाब से आमूल और निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। 2020 से लागू हुई शिक्षा नीति में खेलकूद और बुनियादी कौशल को पाठ्यक्रमों में जोड़कर सुधार के कुछ प्रयास किए गए हैं। परीक्षा प्रणाली को भी तार्किकता और समझ आधारित बनाने की कोशिश की गई है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। भारतीय शिक्षा श्रम के प्रति हीन भावना पैदा करती है। यही उसकी मूल समस्या है। वह छात्रों को रोजगार के लिए नहीं, बाबूशाही और अफसरशाही के लिए तैयार करती है। इसीलिए काम-धंधों के संदर्भ

में पकौड़े या चाय बेचने वाले की मिसाल का भी मजाक उड़ाया जाता है। गांधी जी इसे समझते थे। इसलिए 'नई तालीम' में उन्होंने कौशल केन्द्रित शिक्षा को अनिवार्य बताया था। वही शिक्षा प्रणाली एआइ की चुनौतियों का असली समाधान बन सकती है। इसका प्रमाण जर्मनी की शिक्षा प्रणाली में देखा जा सकता है, जहां किताबी शिक्षा के साथ-साथ कामकाजी और प्रायोगिक शिक्षा का अनूठा संगम है। छात्रों के लिए सातवीं कक्षा से ही कई विकल्प खुल जाते हैं। मसलन वे उच्च अकादमिक संस्थानों के लिए तैयार करने वाले विशिष्ट माध्यमिक स्कूलों में जा सकते हैं, जहां प्रवेश के लिए परीक्षा देनी होती है या सामान्य माध्यमिक स्कूलों में जा सकते हैं, जहां किताबी के साथ-साथ कामकाजी शिक्षा के तमाम विकल्प होते हैं या फिर सीधे कामकाजी स्कूल में या फिर तकनीकी स्कूल में जा सकते हैं, जहां उन्हें रुचि और प्रतिभा के आधार पर विभिन्न काम-धंधों, पेशों और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। इसे दोहरी शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यह किताबी शिक्षा को काम के प्रशिक्षण के साथ मिलाकर चलती है। कामकाजी प्रशिक्षण के लिए हर जिले के उद्योग-धंधों को स्कूलों के साथ जोड़ा गया है, जिससे स्नातकों को अधुनातन कौशल सीखने को मिलते हैं, जिनकी उद्योग-धंधों को जरूरत होती है। छात्रों को काम सीखने के साथ-साथ उसका पैसा भी मिलता है और पढ़ाई के बाद काम मिलने की संभावना भी बढ़ती है। इस प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह है कि छात्रों और समाज में भारत की तरह काम-धंधों के प्रति हीन भावना नहीं है। नाई या बढ़ई के पेशे का भी वही सम्मान है, जो फैशन डिजाइनर या दंत चिकित्सक का है। यही वजह है कि जर्मनी में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। भारत को भी ऐसी ही शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा सुधारों पर गंभीर चर्चा करने की जगह हमारी संसद में खाली शोर मचता है, जो देश की युवा पीढ़ी के मातम की तरह है।

प्यूपिल्स टाइम्स
विशेष शोध-श्रृंखला

भाग-2

आंदोलन कहाँ से उभरा ?-जब पुस्तकालयों से निकली आवाज राष्ट्रीय विमर्श बनी
'प्रत्येक आंदोलन का एक भौगोलिक स्थान होता है, पर उसका वास्तविक जन्म उस क्षण होता है जब हजारों लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्या वास्तव में एक साझा अनुभव है।' यदि इतिहास के पन्नों को ध्यान से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि बड़े जन-आंदोलनों की शुरुआत प्रायः किसी विशाल जनसभा से नहीं होती। वे किसी विश्वविद्यालय के परिसर, किसी छोटे कस्बे, किसी कारखाने, किसी खेत या किसी पुस्तकालय में जन्म लेते हैं। प्रारम्भ में वे कुछ लोगों की चिंता प्रतीत होते हैं, लेकिन समय के साथ वही चिंता व्यापक सामाजिक प्रश्न बन जाती है।

2026 का छात्र आंदोलन भी इसी प्रक्रिया का उदाहरण माना जा सकता है

यह कहना कठिन है कि इस आंदोलन का जन्म किसी एक शहर या किसी एक दिन हुआ। उपलब्ध सार्वजनिक घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि देश के अनेक प्रतियोगी शिक्षा केंद्रों में लगभग एक ही समय पर परीक्षा-प्रक्रियाओं को लेकर प्रश्न उठने लगे। दिल्ली का मुखर्जी नगर, प्रयागराज, कोटा, पटना, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर तथा अन्य शिक्षा केंद्र इस चर्चा के प्रमुख सार्वजनिक मंच बनकर उभरे। इसलिए इस आंदोलन को किसी एक भौगोलिक बिंदु से जोड़कर देखने के बजाय उसे एक समानांतर राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा।

2026 का छात्र-आंदोलन : कक्षा से संसद तक नागरिक सक्रियता का नया समाजशास्त्र

कोचिंग नगर : केवल शिक्षा केंद्र नहीं, सामाजिक प्रयोगशालाएँ
पिछले दो दशकों में भारत के अनेक शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के राष्ट्रीय केंद्र बन गए हैं। इन नगरों की अपनी एक विशिष्ट सामाजिक संरचना है। यहाँ देश के लगभग प्रत्येक राज्य से विद्यार्थी आते हैं। वे अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखते हैं, लेकिन उनके सपने लगभग एक जैसे होते हैं। इन शहरों में छात्र केवल पढ़ते नहीं हैं; वे साथ रहते हैं, चर्चा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और एक-दूसरे की सफलताओं तथा असफलताओं से सीखते हैं। यही कारण है कि यहाँ किसी एक विद्यार्थी की समस्या बहुत शीघ्र ही अनेक विद्यार्थियों की साझा चिंता बन जाती है। समाजशास्त्र की भाषा में इसे "Shared Social Space" कहा जा सकता है-ऐसा सामाजिक वातावरण जहाँ समान अनुभव सामूहिक चेतना का निर्माण करते हैं। **आकांक्षी भारत का नया चेहरा**
इन कोचिंग नगरों में रहने वाला अधिकांश छात्र भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आज Aspirational India कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है- जिसके परिवारों ने शिक्षा को सामाजिक उन्नति का सबसे विश्वसनीय माध्यम माना। जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं को अवसर की समानता का प्रतीक समझा। जिसने डिजिटल तकनीक को स्वाभाविक जीवन का हिस्सा बनाया। और जिसने पारदर्शिता को सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखना प्रारम्भ

किया। यह वर्ग किसी विशेष विचारधारा से नहीं, बल्कि अपने भविष्य से प्रेरित होता है। इसी कारण जब परीक्षा-प्रक्रिया से जुड़े प्रश्न उठे, तो उनकी प्रतिक्रिया भी वैचारिक संघर्ष के बजाय संस्थागत स्पष्टता की मांग के रूप में सामने आई।

व्यक्तिगत अनुभव से सामूहिक अनुभव तक
प्रारम्भिक दिनों में अनेक विद्यार्थियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव एक-दूसरे से साझा किए। किसी ने परीक्षा केंद्र की तकनीकी समस्या पर प्रश्न उठाया, किसी ने मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता व्यक्त की, किसी ने शिकायत-निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की बात कही। इन अनुभवों की सत्यता प्रत्येक मामले में अलग-अलग हो सकती थी, परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि हजारों विद्यार्थियों को लगा कि उनकी जिज्ञासाएँ और चिंताएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। यहीं से व्यक्तिगत अनुभव सामूहिक अनुभव में परिवर्तित होने लगा।

लाइब्रेरी : अध्ययन का स्थान या संवाद का मंच ?

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं होते। वे विचार-विनिमय, सूचना-साझाकरण और सामाजिक संवाद के केंद्र भी होते हैं। कई पुस्तकालयों में दिनभर की पढ़ाई के बाद होने वाली चर्चाएँ केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहतीं। वे परीक्षा प्रणाली, नीति, रोजगार, मानसिक दबाव और भविष्य की

संभावनाओं तक पहुँच जाती हैं। 2026 के घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि यही पुस्तकालय अनेक स्थानों पर सार्वजनिक विमर्श के प्रारम्भिक केंद्र बन गए। यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चाएँ पहुँचीं, और वहीं से वे राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने लगीं।

डिजिटल नेटवर्क ने दूरी मिटा दी

यदि यह घटनाक्रम एक दशक पहले होता, तो संभवतः अलग-अलग शहरों के छात्र एक-दूसरे के अनुभवों से शीघ्र परिचित नहीं हो पाते। लेकिन 2026 तक भारत का डिजिटल परिदृश्य बदल चुका था। टेलीग्राम समूह, व्हाट्सएप समुदाय, यूट्यूब चैनल, एक्स (पूर्व ट्विटर) और अन्य डिजिटल मंचों ने विभिन्न शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को लगभग वास्तविक समय में जोड़ दिया। इससे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, सूचना का प्रसार अत्यंत तीव्र हो गया। दूसरा, समान अनुभव रखने वाले विद्यार्थियों को यह महसूस होने लगा कि वे अकेले नहीं हैं। यही भावना किसी भी सामाजिक आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विश्वास और संवाद का प्रश्न

यह समझना आवश्यक है कि प्रारम्भिक चरण में अधिकांश छात्र व्यवस्था के विरोध में नहीं, बल्कि व्यवस्था से संवाद के पक्ष में दिखाई दिए।

उनकी प्रमुख अपेक्षाएँ थीं-

» प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाया जाए।

» तकनीकी प्रश्नों का समयबद्ध उत्तर दिया जाए।

» शिकायतों का पारदर्शी समाधान उपलब्ध हो।

» परीक्षा संचालन से संबंधित सूचनाएँ अधिक सुलभ

हों।

» इन मांगों का स्वर क्रांतिकारी नहीं, बल्कि प्रशासनिक था।

» यही कारण है कि प्रारम्भिक चरण में इस आंदोलन को अनेक शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों की सहानुभूति भी प्राप्त हुई।

समाजशास्त्रीय निष्कर्ष

किसी भी आंदोलन का वास्तविक जन्म उस दिन नहीं होता जब लोग सड़क पर उतरते हैं। उसका जन्म उस दिन होता है जब समाज का एक वर्ग यह महसूस करता है कि उसकी चिंता व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक है। 2026 का छात्र आंदोलन इसी परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसने यह संकेत दिया कि भारत का आकांक्षी युवा केवल अवसर नहीं चाहता; वह अवसर की प्रक्रिया को भी समझना और उस पर विश्वास करना चाहता है। यही कारण है कि इस आंदोलन को केवल परीक्षा-संबंधी असंतोष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह संस्थागत विश्वास, डिजिटल नागरिकता और लोकतांत्रिक संवाद के बदलते संबंधों का भी अध्ययन है।

Pupils Times का दृष्टिकोण

जब कोई समाज अपने युवाओं की जिज्ञासाओं को गंभीरता से सुनता है, तब वह केवल एक समस्या का समाधान नहीं करता; वह भविष्य के प्रति विश्वास का निर्माण करता है।

2026 का छात्र आंदोलन इसी विश्वास की खोज का प्रारम्भिक अध्याय है।...अगला अध्याय भाग-3 में...

महाराष्ट्र में स्कूलों के मिड-डे मील पर एफडीए की सख्ती, नए नियम लागू

50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक



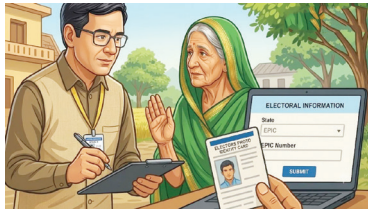
मुंबई: महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़े फैसले लिए हैं। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मिड-डे मील और कैंटीन संचालन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुकाराम मुंडे ने बताया कि महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर एफडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि 18 प्रकार की फूड कैटेगरी के आधार पर निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य में करीब 1.08 लाख स्कूल हैं और इन स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के

लिए वर्ष 2020 में नियम बनाए गए थे, लेकिन कई संस्थानों को इन नियमों की जानकारी नहीं है। इसलिए अब इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन मिल सके। एफडीए के नए आदेश के तहत महाराष्ट्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, स्कूल कैंटीन और मिड-डे मील संचालकों के लिए एफएसएसआई का लाइसेंस या पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा, स्कूल परिसर के बाहर 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अत्यधिक मीठे उत्पाद और अन्य प्रोसेस्ड या पैकेज्ड जंक फूड शामिल हैं। हर स्कूल

में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नियुक्त करने की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। एफडीए समय-समय पर स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की जांच करेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने हाल ही में राज्य के पांच बड़े क्लबों पर की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान इन क्लबों में कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। मुंडे के अनुसार, कई जगहों पर कॉकरोच पाए गए, साफ-सफाई की स्थिति खराब थी और शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन तैयार करने के लिए अलग-अलग सेक्शन नहीं थे। इसके अलावा भी खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आईं, जिसके आधार पर संबंधित क्लबों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि एफडीए का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों सहित सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो।

SIR ड्यूटी से अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई

बीएमसी और बिजली वितरण के अधिकारियों पर एफआईआर



बिरेन्द्र शर्मा/प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबई: बांद्रा पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव उप तहसीलदार की शिकायत पर बीकेसी पुलिस ने, बीएमसी के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग (जी/दक्षिण प्रभाग) के कार्यकारी सहायक अतुल निवृत्ति वाघमारे और महावितरण के उप प्रबंधक मनोज वसंतराव कुलकर्णी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि चुनाव आयोग की ऑनलाइन प्रणाली पर पंजीयन के बाद वे न तो किसी समीक्षा बैठक में शामिल हुए, और न ही अपने आवंटित कार्य का पर्यवेक्षण किया। वे चुनाव ड्यूटी से गायब थे।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का कार्य जोर-शोर से जारी है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान के दौरान एक तरफ जहां प्रशासन लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त

रुख अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और शिक्षकों पर अत्यधिक मानसिक व शारीरिक तनाव की बातें भी कही जा रही हैं। प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है। चुनाव उप तहसीलदार की शिकायत पर हुई इस प्राथमिकी से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी कर्तव्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

हाल ही में चेदूर कैप हिंदी स्कूल के 37 वर्षीय शिक्षक कैलाश भोयर की बीएलओ ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से दुखद मृत्यु हो गई। इसके अलावा, घाटकोपर में स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं के बावजूद ड्यूटी से राहत न मिलने पर एक शिक्षिका द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला भी सामने आया है। घर-घर जाकर सत्यापन करने और फॉर्म भरवाने के इस कठिन कार्य से शिक्षकों पर चौराफरा दबाव बन रहा है। जिससे स्कूलों में पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चलाए जा रहे इस अभियान के लिए राज्यभर में 1,00,253 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तैनात किए गए हैं। जिनमें से अकेले मुंबई में 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं।

राज्य में 1.70 करोड़ परिवारों के लिए QR कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड

गौरव सिंह/प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबई: राज्य के नागरिकों को ज्यादा आसान, सुरक्षित और मॉडर्न राशन कार्ड देने के मकसद से, दफ कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड देने का फैसला किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छगन भुजबल ने येओला, (नासिक जिला) में एक प्रोग्राम में हर योग्य नागरिक के लिए दफ कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड की कॉपी दिखाई। इस कैम्पेन के तहत, राज्य में लगभग 1.70 करोड़ परिवारों को दफकोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राशन कार्ड सिस्टम में ज्यादा आसानी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने में मदद मिलेगी, और नागरिक सरकारी खाद्य वितरण सिस्टम की सेवाओं का ज्यादा आसानी से फायदा उठा



पाएंगे। स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्मार्ट राशन कार्ड प्रोजेक्ट को लागू करने की पहल की थी। राज्य के गरीब और आम लोगों को पुराने कागज के राशन कार्ड की वजह से होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने उन्हें दफकोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड देने का निर्देश दिया था। उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, राज्य के लोगों को स्मार्ट राशन कार्ड देने के लिए अगले तीन सालों में 'स्वर्गीय अजीतदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का कैम्पेन' लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत, 'नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम (AAY और PHH)' के साथ-साथ APL-शेतकरी स्कीम के राशन कार्ड होल्डर्स को दफकोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड मुफ्त में दिए जाएंगे।

मुंबई में बेस्ट बसों की हालत पर सवाल

मुंबई: मानसून के बीच मुंबई की बेस्ट बसों के रखरखाव और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बेस्ट समिति सदस्यों ने आरोप लगाया है कि शहर में चल रही कई बसें खराब दरवाजों, बारिश में पानी रिसने और रखरखाव की खामियों से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि प्रस्थान से पहले निरीक्षण के दावों के बावजूद ऐसी बसें सड़कों पर उतर रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा और सुरक्षा संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, बेस्ट प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी बसों का नियमित निरीक्षण किया जाता है और हालिया अधिकांश दुर्घटनाएं तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि मानवीय त्रुटि का परिणाम थीं। शिवसेना (यूबीटी) के नेता व बेस्ट समिति सदस्य नितिन नंदगांवकर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में रूट 357



शिवाजी नगर-मुंबई सेंट्रल की एसी बस में सफर किया, जहां दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि इससे एसी सेवा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है, जबकि यात्री इसके लिए न्यूनतम 12 रुपये किराया चुकाते हैं। नितिन का आरोप है कि पिछले सप्ताह प्रशासन ने 27 डिपो से बसें रवाना होने से पहले जांच का भरोसा दिया था, लेकिन खराब बसें अब भी सड़कों

पर हैं, नंदगांवकर ने बेस्ट के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में 868 बसों में खराबियां पाई गईं, जिनमें से 774 बसों की मरम्मत पिछले तीन महीनों में की गई। उनके अनुसार, यह आंकड़ा बताता है कि विशेषकर मुंबई मानसून में रखरखाव की और कड़ी निगरानी की जरूरत है। उन्होंने हालिया बस दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल चालक की गलती बताकर तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं, बेस्ट के इंजीनियरिंग और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सभी बसों की नियमित जांच और रखरखाव किया जाता है। हालिया दुर्घटनाओं की जांच में वाहन तकनीकी रूप से सुरक्षित पाए गए हैं और अधिकांश घटनाएं मानवीय भूल के कारण हुईं।

हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद कब्जे की कोशिश का आरोप

चुनार के भौरही गांव में विवादित भूमि को लेकर सीओ से न्यायालय के आदेश के पालन की मांग

प्यूपिल्स टाइम्स/ मिर्जापुर विशेष

मिर्जापुर: चुनार तहसील के ग्राम भौरही स्थित एक विवादित भूमि को लेकर नया विवाद सामने आया है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के स्पष्ट अंतरिम आदेश के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा भूमि की मौजूदा स्थिति बदलकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी (सीओ) चुनार को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित कराने तथा विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की गई है।

प्रार्थी शरदेंदु कुमार पाण्डेय उर्फ शरद कुमार, निवासी जफराबाद, रोहनिया (वाराणसी), के अनुसार ग्राम भौरही, परगना हवेली स्थित आराजी संख्या 475/1, रकबा 12 बिस्वा



15 धूर उनकी भूमि है। इस भूमि से संबंधित विवाद रिट-बी संख्या 1288/2026, "शरदेंदु कुमार पाण्डेय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य" के रूप में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रार्थी का कहना है कि 4 मई 2026 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि "अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि की प्रकृति एवं कब्जे की स्थिति यथावत बनाए रखी जाए।" इसके बावजूद आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने ट्रैक्टर

से जुताई कराकर भूमि की वर्तमान स्थिति बदलने तथा कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे न्यायालय के आदेश की भावना प्रभावित हुई।

प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ न्यायालय के आदेश की प्रति तथा घटनास्थल के छायाचित्र भी संलग्न किए हैं और प्रशासन से विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति सुरक्षित रखने तथा किसी भी अवैध हस्तक्षेप को रोकने की मांग की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामला संज्ञान में है और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

अस्वीकरण: यह समाचार प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों पर आधारित है, आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया के उपरांत ही होगी।

बारिश को लेकर मुंबई मनपा 33 जगहों पर फ्लड गेट लगाएगा



मुंबई: मुंबई में हर साल भारी बारिश की वजह से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 13,000 करोड़ रुपये का एक इटीग्रेटेड फ्लड कंट्रोल प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत, मुंबई में 33 और जगहों पर फ्लड गेट और पंपिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। नदियों और बड़े नालों में पानी का लेवल मापने के लिए एक एडवांस्ड सेंसर सिस्टम लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि पूरा प्लान अक्टूबर 2029 तक पूरा करने का प्लान है इस बड़े फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट

को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विधानसभा को बताया था कि फंडिंग के लिए एक प्रपोजल भी केंद्र को भेजा गया है। 26 जुलाई, 2005 को मुंबई में एक ही दिन में 944 बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस बाढ़ के बाद, टुथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, ब्रिमस्टोवाड प्रोजेक्ट के तहत स्टॉर्म वॉटर चैनल्स को चौड़ा और गहरा करने, फ्लड चैनल्स, अंडरग्राउंड नालों की मरम्मत और पंपिंग स्टेशन बनाने जैसे कई कामों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए। हालांकि, शहर में पानी भरने वाले इलाकों की संख्या उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुई है। नए प्लान के पहले फेज में माहुल और मोगरा पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ-साथ मीठी नदी के तीसरे फेज में 18 फ्लड गेट, सर्विस रोड और सुरक्षा दीवारें बनाने का काम शुरू किया जाएगा इसके अलावा, मुंबई में 33 और जगहों पर फ्लड गेट और पंपिंग सिस्टम लगाए जाएंगे।

महाराष्ट्र कैबिनेट के 8 बड़े फैसले

अवैध खनन पर 10 गुना जुर्माना, 5 जिलों में नए न्यायालय को मंजूरी



पांच जिलों में नए न्यायालय

■ पुणे में एनडीपीएस मामलों के लिए विशेष न्यायालय, सोलापुर के कुडूवाडी में दीवानी न्यायालय और अहिल्यानगर के कर्जत में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड और यवतमाल में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए अन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित होंगे।

कृषि में AI को बढ़ावा

■ महा एग्री एआई नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एग्रीटेक नवाचार केन्द्र में प्रबंध निदेशक के पद को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है

कि इससे 500 करोड़ की इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को नई गति मिलेगी।

मुंबई: सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने बैठक में बुनियादी ढांचे को। गति देने और आम जनता को त्वरित न्याय के लिए न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया। अवैध गौण खनिज उत्खनन और उसके परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रॉयल्टी का 10 गुना भारी जुर्माना वसूलने का बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और

परिवहन के मामलों में रॉयल्टी की 10 गुना राशि तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। रेलवे विकास, स्थानीय स्वराज संस्थाओं, न्यायालयों के विस्तार और कृषि क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने जैसे निर्णय लेकर सरकार ने विकास और न्यायिक ढांचे

को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। मुंबई रेलवे विकास महामंडल की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ की गई। आरक्षित सीटों से चुने गए ग्रांप, जिप और पस के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 12 माह के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है।

छात्रों को नहीं करना पड़ेगा दीक्षांत समारोह का इंतजार डिजिटल आते ही डिजिलॉकर पर मिलेंगे छात्रों को डिग्री

नागपुर: नागपुर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को जून 2026 तक आयोजित सभी परीक्षाओं के परिणाम और शैक्षणिक क्रेडिट (श्रेयांक) विद्यार्थियों की अपार आईडी से जोड़कर 31 जुलाई तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने दिए हैं। साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद दीक्षांत समारोह का इंतजार किए बिना विद्यार्थियों के डिग्री एवं डिप्लोमा प्रमाणपत्र डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में राज्यभर की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में 'एक देश, एक विद्यार्थी पहचान' नीति के तहत अपार आईडी और डिजिलॉकर की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि राज्य में अब तक 2.67 करोड़ विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं 39.67 लाख शैक्षणिक क्रेडिट सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। दरअसल, परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाणपत्र के लिए दीक्षांत समारोह का इंतजार करना पड़ता है। इससे उच्च शिक्षा,



विभिन्न प्रवेश प्रक्रियाओं तथा विदेश में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों को समय पर प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जून 2026 तक आयोजित सभी परीक्षाओं के परिणाम और शैक्षणिक क्रेडिट 31 जुलाई तक विद्यार्थियों की अपार आईडी से लिंक कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं, साथ ही दीक्षांत समारोह की प्रतीक्षा किए बिना डिग्री और डिप्लोमा प्रमाणपत्र डिजिलॉकर पर जारी किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को समय पर डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध हो सकें, इसके अलावा विद्यार्थियों के सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और शैक्षणिक क्रेडिट को सुरक्षित एवं अद्यतन रखने के लिए डिजिलॉकर का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

डब्बावालों को चिकित्सा उपचार के लिए महापौर चिकित्सा सहायता निधि से

तत्काल ₹25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी



अनुराग शुक्ला/प्यूपिल्स टाइम्स
मुंबई: मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने मुंबई डब्बावाला संघ (मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन) की विभिन्न मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि महानगरपालिका डब्बावालों की सभी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पंजीकृत डब्बावालों को चिकित्सा उपचार के लिए महापौर चिकित्सा सहायता निधि से तत्काल ₹25 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बीमारी या इलाज के खर्च से जूझ रहे डब्बावालों

और उनके परिवार को इस योजना से आर्थिक सहारा मिलेगा। डब्बावाले मुंबई की लाइफलाइन माने जाते हैं और लाखों लोगों को समय-समय पर खाना पहुंचाते हैं। इस घोषणा से डब्बावाला समुदाय में खुशी की लहर है। सरकार ने कहा कि यह मदद उनकी मेहनत और सेवा को सम्मान देने के लिए है। महापौर रितु तावड़े ने कहा कि मुंबई के डब्बावाले केवल एक सेवा नहीं, बल्कि शहर की श्रम संस्कृति और अनुशासन के प्रतीक हैं। उनकी कार्यप्रणाली दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों के लिए प्रेरणा रही है।

पूर्व सैनिकों के लिए सौगात: समीक्षा बैठक में बोले शंभूराज देसाई

सातारा और पंढरपुर में बनेंगे अत्याधुनिक परिसर

मुंबई: राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार अब सातारा और पंढरपुर में महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल तथा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की जमीन पर विकास कार्य तेज गति से होगा। यहां पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक परिसर बनाए जाएंगे। यह जानकारी पर्यटन, खान एवं पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई ने दी।

मंत्री देसाई ने बताया कि सातारा में बनने वाले परिसर में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की पत्नियों द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी। इससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य की पहली ऐसी एकीकृत विकास परियोजना होगी, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक नया उदाहरण बनेगी। मुंबई के सहाय्यी अतिथि गृह में मंत्री शंभूराज देसाई की अध्यक्षता में इस परियोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सातारा और पंढरपुर स्थित



MTDC तथा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की भूमि के संयुक्त विकास कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया। बैठक में पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव संतोष कुमार, MTDC के प्रबंध निदेशक नीलेश गटणे और उप सचिव विजय पोवार उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे संभाग के पूर्व सैनिक कल्याण निदेशक, सातारा के जिलाधिकारी, सोलापुर के निवासी उप जिलाधिकारी, पंढरपुर मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सातारा-सोलापुर

के जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी भी बैठक से जुड़े। बैठक में पंढरपुर में बनने वाले आधुनिक परिसर की योजना की विस्तार से समीक्षा की गई। इस परिसर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आवास, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, सरकारी सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को दोनों स्थानों की जमीन की मौजूदा स्थिति, स्थल निरीक्षण, उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और संयुक्त विकास की योजना पर विस्तृत चर्चा के बाद आवश्यक निर्देश दिए। शंभूराज देसाई ने कहा कि राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार इस परियोजना में पर्यटन विकास के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना की बेहतर योजना बनाने, सभी विभागों में समन्वय रखने और काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विश्वास जताया कि यह परियोजना राज्य में पूर्व सैनिकों के कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।

Result Guarantee Above 90% or Money Back

If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things

Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy

MUMBAIHOME & PRIVATE TUITIONS

1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / WJEC / State Boards

XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET

Engg, Degree, Diploma, B.Com, B.Sc., BMS,

MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking

Any Class Home Tuitions Across Mumbai

Get Admission in MBBS

NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs

ADMISSIONS OPEN

Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Vihar

Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur

Home Tuitions Benefits

Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153

https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS
PROPERTIES

Beyond Dreams

BUY | SELL | RENT

FLATS • SHOPS • BUNGALOWS

LANDS • REDEVELOPMENT

Trusted Property Consultant

Residential & Commercial Deals

Best Market Price Assistance

Contact:

+91 9167378057

Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC

Ambernath (W), Maharashtra

Nursing Home Reg. No.: THN-C274*

FACILITIES AVAILABLE

✓ 24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support

✓ Diabetology & Advanced Diabetic Care

✓ Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)

✓ Cardiology Checkup & ECG Facility

✓ General Medicine Consultation

✓ Vaccination & Immunization Services

✓ Minor Surgical Procedures

✓ OPD & IPD Care Available

✓ Complete Health Checkups

24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE

+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambarnath West, Thane

Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

DR. ZUBER S. SHAH

M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)

Cert. in Diabetology & Emergency Medicine



■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व
आयुर्वेदिक दवाखाना

शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। कई लोगों को बीमार न होने पर भी शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर इसे ठीक न किया जाए, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। इसका

आयुर्वेद के अनुसार शरीर की अतिरिक्त गर्मी को प्राकृतिक रूप से कम करने के उपाय

सबसे अच्छा समाधान आयुर्वेद के ऐसे उपाय हैं जो बिना किसी नुकसान के मदद करते हैं। आयुर्वेद शरीर की ज्यादा गर्मी को पित्त दोष का बढ़ना मानता है, जो शरीर के तापमान, पाचन और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इस समस्या के कारण हाइपरथर्मिया (बिना संक्रमण के शरीर की गर्मी बढ़ना) या गर्मी के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। इसके कारणों में हार्मोनल असंतुलन, तेज मेटाबॉलिज्म या उम्र भी शामिल हो सकते हैं। कई बार तनाव, चिंता, खान-पान और जीवनशैली में बदलाव जैसे मसालेदार खाना, शराब और कैफीन, सिंथेटिक कपड़े और आसपास का माहौल भी इसके कारण हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस ज्यादा गर्मी से निपटने के लिए आयुर्वेद पर आधारित घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।



शरीर की ज्यादा गर्मी के इलाज के लिए चार आयुर्वेदिक घरेलू उपाय

सत्तू का आटा: 'थोड़ा सत्तू (जौ या भुना हुआ चना) लें। इसमें थोड़ा शहद और पानी मिलाकर पतला सत्तू ड्रिंक बनाएं। अगर आप यह पतला सत्तू वाला पानी पीते हैं, तो यह मूत्रवर्धक (diuretic) होता है, गर्मी को शांत करता है और टंडक, पोषण और फायदे देता है।'

धनिया का पानी: धनिया के बीज शरीर को अंदर

से ठंडा रखने और बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने में प्राकृतिक रूप से असरदार होते हैं। यह पाचन और तापमान से जुड़ी समस्याओं जैसे हॉट फ्लैशेस और एसिडिटी को नियंत्रित करता है। दो से तीन चम्मच धनिया के बीज रात भर पानी में भिगोकर रखें। अगली सुबह इस पानी को छान लें और टंडक पाने के लिए पिएं। टंडक के असर के लिए पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं।

नारियल पानी: इसे रोज पिएं, क्योंकि यह शरीर की गर्मी की समस्याओं से निपटने में मदद करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हुए खोए हुए मिनरल्स और हाइड्रेशन को फिर से पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बेहतरीन स्रोत है। ज्यादा टंडक के लिए इसमें पुदीना

मिलाएं। या फिर गर्मी कम करने और शरीर के अंदर की सूजन को ठीक करने के लिए नारियल पानी और छने हुए खीरे के रस का ड्रिंक बनाएं। गर्मी से राहत पाने और साथ ही विटामिन उ और बेहतर पाचन के लिए आप इसमें नींबू या लाइम का रस और संतरे के टुकड़े भी मिला सकते हैं।
एलोवेरा जूस: एलोवेरा से आपको शरीर के अंदर और बाहर की गर्मी से राहत पाने के लिए एक नैचुरल और ठंडा करने वाला विकल्प मिलता है। एक गिलास पानी में दो बड़े चम्मच एलोवेरा मिलाएं और टंडक के लिए इसे खाली पेट पिएं। या फिर एलोवेरा जेल को खीरे और पुदीने की पत्तियों के साथ मिलाकर नींबू पानी में मिलाएं। यह गर्मी से राहत देते हुए आपको ताजगी देता है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

सावन महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है

सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जात है। पुराणों में इस महीने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस महीने में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग और जल चढ़ाने से कई गुने फल की प्राप्ति होती है। सावन में शिव आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सावन में पूजा, ध्यान, जप, तप और दान करने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। श्रावण का महीना हिंदू कैलेंडर का पांचवां महीना होता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है, जो पूर्णिमा तिथि तक चलता है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-आराधना का विशेष महत्व होता है। सावन के महीनों शिव मंदिरों में भारी

श्रावणे मासि यो भक्त्या शिवलिंग प्रपूजयेत्।
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥



भीड़ एकत्रित होती हैं जहां पर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, गन्ने का रस, भांग, भस्म और आक के फूल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में भगवान

शिव की पूजा करने और जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव के आराधना का सावन महीना 30 जुलाई 2026 को शुरू होगा। इस महीने आस्था, भक्ति और साधना का विशेष महत्व है। यह

कब से सावन शुरू

■ हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई को रात 08 बजकर 05 मिनट से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 30 जुलाई को रात 9 बजकर 30 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार श्रावण महीने की शुरुआत 30 जुलाई, गुरुवार के दिन से होगी। श्रावण महीने का समापन 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा तिथि पर होगा। इस वर्ष सावन महीने में कुल 31 दिन होंगे।

सावन सोमवार तिथियां

■ इस वर्ष श्रावण माह में कुल 4 सावन सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा-आराधना और जलाभिषेक किया जाता है। 30 जुलाई, गुरुवार से सावन का महीना शुरू होगा और सावन का पहला सोमवार, 3 अगस्त, सावन का दूसरा सोमवार, 10 अगस्त, सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को है।

पवित्र महीना 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान वातावरण भी भक्ति और उत्साह से सराबोर रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी काल में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके

बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यही कारण है कि सावन का महीना शिव-पार्वती के पावन मिलन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। सावन के सोमवार का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है।

पेज-1 का शेष

दुश्मन पनडुब्बियों की अब खैर नहीं...

इस श्रेणी के युद्धपोत भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा को और सशक्त बनाएंगे। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद 'मछलीपटनम' समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके शामिल होने से नौसेना की परिचालन तैयारियों को और मजबूती मिलेगी तथा देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और प्रभावी होगी।

रक्षा मंत्री ने 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान को पूरा करने पर...

आईएसवी त्रिवेणी की टीम का मुंबई में 22 जुलाई को रक्षा मंत्री ने वर्चुअली स्वागत किया। उन्होंने 11 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस यात्रा की शुरुआत (फ्लैग-ऑफ) समारोह में हिस्सा लिया था।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा...

जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। भारत के व्यापक आर्थिक प्रदर्शन के बारे में गोयल ने कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसने विश्व भर में बहुत सारी अनिश्चितताओं के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में 7 दशमलव 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया...

यह उपलब्धि भारत के समुद्री क्षेत्र के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है। 2015 में, भारत ने विश्व के नाविकों में केवल 5.2 प्रतिशत का योगदान दिया और चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया और रूसी संघ के बाद विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर रहा। छह साल बाद, 2021 में, भारत की हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई, हालांकि यह पांचवें स्थान पर बनी रही। हालांकि, नवीनतम BIMCO-ICS रिपोर्ट एक निर्णायक सफलता दर्ज करती है।

Your Dreams Destination is here

Pushpam Classes

Classes Also Available on Online Platforms

CBSE ICSE NIOS MUMBAI BOARD

English • Hindi • Marathi Medium
I to XII (Science / Commerce / Arts)

COMPETITIVE EXAMS PREPARATION

Pravinya • Mathex • CV Raman • Science Exam • IPM •
NTSE • NLSTSE • Olympiads KVPY & More

✓ Experienced Faculty
✓ Small Batches & Focused Attention
✓ Regular Tests & Doubt Solving
✓ Excellent Results Every Year

Contact Now:
+91 9220868564
+91 9320868564

Join Us for Academic Excellence!

Step into the Future with ASR Digi!

Imagine exploring properties, products, and places without leaving your home! With our state-of-the-art Virtual Reality Tours, your audience can experience your offerings like never before.

Our Services Include:

- Immersive Virtual Tours
- Captivating Drone Videography
- Realistic 3D Renders
- Scale Models
- Influencer & YouTube Marketing
- Professional Website Development
- Side Branding with LED Screens

Don't just tell your Story-show it in stunning detail!

Contact us today!
Satish Pandey from Navi Mumbai
8879895829 / 9619574572

www.asrdigi.com

भारतस्य रहस्यमयं शैलाभिलेखम् : रत्नागिरेः प्रागैतिहासिक-शैलोत्कीर्णनानि विंशतिसहस्रवर्षेभ्यः अपि प्राचीना पाषाणभाषा, या अद्यापि इतिहासस्य नूतनान् प्रश्नान् जनयति



प्यूपिल्स टाइम्स/धरोहर-विशेषः
स्कॉटलैण्डदेशस्य प्रसिद्धस्य Cochno Stone इव भारतेऽपि अद्वितीया प्रागैतिहासिकी धरोहरः विद्यते। महाराष्ट्रराज्यस्य रत्नागिरि-जनपदे विस्तीर्णानि शैलोत्कीर्णनानि (Petroglyphs) विश्वस्य महत्त्वपूर्णेषु पुरातात्विकस्थलेषु परिगण्यन्ते। मुक्तशिलासु उत्कीर्णानि एतानि चित्राणि प्रागैतिहासिकमानवानां जीवनम्, प्रकृतिसम्बन्धम्, कलाबोधम्, चिन्तनपरम्परां च सजीवं प्रकाशयन्ति। रत्नागिरि-राजापुर-

लाञ्छा-सङ्गमेश्वर-प्रदेशेषु लेटराइट-शिलासु निर्मितानाम् एतेषां शैलचित्राणां व्यवस्थितम् अध्ययनं विंशतिशतकस्य नवमे दशके (१९९०-दशके) आरब्धम्। अधुना कोंकणप्रदेशस्य पञ्चाशदधिकेषु ग्रामेषु सहस्रत्रिशताधिकानि शैलोत्कीर्णनानि अभिलेखितानि सन्ति। तेषु हरिणाः, गण्डकाः, कूर्माः, मत्स्याः, मानवाकृतयः, पदचिह्नानि, वृत्तानि, भूलभुलैयासदृशाः ज्यामितीयविन्यासाः तथा अन्येऽपि रहस्यमयाः

प्रतीकाः दृश्यन्ते। पुरातत्त्वविदः सामान्यतया एतानि शिलोत्कीर्णनानि दशसहस्रात् विंशतिसहस्रवर्षपर्यन्तं प्राचीनानि मन्यन्ते, यद्यपि केचन शोधाः तेषामधिकप्राचीनतामपि सूचयन्ति। एतेषां प्रत्यक्षं कार्बन-काल-निर्धारणम् अशक्यमस्ति; अतः तेषां प्राचीनता पुरातात्विकप्रमाणैः, भूवैज्ञानिक-अध्ययनैः तथा प्राप्तावशेषैः निर्धार्यते। एतानि शैलोत्कीर्णनानि केवलं कलाकृतयः न, अपितु भारतस्य आदिमसभ्यतायाः जीवनशैल्याः, पर्यावरणबोधस्य, सांस्कृतिकविकासस्य च मौनसाक्षिणः सन्ति। वर्षा, प्राकृतिकक्षयः, अतिक्रमणं च एतेषां संरक्षणाय गम्भीराण्याव्हानानि सन्ति। अतः एतेषां वैज्ञानिकसंरक्षणं केवलं पुरातत्त्वविद्यायाः विषयः न, अपितु भारतस्य प्राचीनसभ्यतायाः अमूल्यविरासतां भाविपीढीभ्यः सुरक्षितं कर्तुं राष्ट्रीयं दायित्वम् अस्ति। Pupils Times इत्यस्य मतम्-शिलासु उत्कीर्णानि एतानि चित्राणि केवलं प्राचीनकलायाः अवशेषाः न सन्ति, अपितु मानवसभ्यतायाः आद्यस्मृतयः सन्ति। यः समाजः स्वस्य अतीतं रक्षति, स एव स्वस्य भविष्यं दृढतया निर्मातुं समर्थः भवति।

जॉन्सन एण्ड जॉन्सन-समवायस्य ५.५ अब्ज-डॉलर-मूल्यस्य समाधान-प्रस्तावः

टैल्क-चूर्णसम्बद्धानां प्रायः ६९,००० न्यायप्रकरणानां निस्तारणाय महत्त्वपूर्ण पहलः

प्यूपिल्स टाइम्स/वैश्विक-व्यापार-विशेषः
अमेरिकादेशस्य विख्यातः स्वास्थ्योपकरण-निर्माता जॉन्सन एण्ड जॉन्सन इति समवायः स्वस्य टैल्क-आधारित-शिशुचूर्णसम्बद्धानां प्रायः ६९,००० न्यायप्रकरणानां निस्तारणार्थं ५.५ अब्ज-अमेरिकी-डॉलर (प्रायः ४६ सहस्र-कोटि भारतीय-रूप्यकाणि) मूल्यस्य समाधान-प्रस्तावं कृतवान्। एषः विवादः गतपञ्चदशवर्षेभ्यः अमेरिकादेशस्य सङ्घीय-न्यायालयेषु तथा विभिन्न-राज्य-न्यायालयेषु प्रवर्तमानः अस्ति। वादिनां आरोपः अस्ति यत् समवायस्य टैल्क-चूर्णस्य उपयोगेन अनेकासु महिलासु अण्डाशय-कर्करोगः (Ovarion Cancer) अभवत् तथा च तस्मिन् चूर्णे एस्बेस्टस (Asbestos) इति स्वास्थ्यहानिकरः पदार्थः मिश्रितः आसीत्। समवायः तु एतान् सर्वान् आरोपान् निराधारान् मन्यते



तथा स्वोत्पादानि वैज्ञानिक-परीक्षणेषु सुरक्षितानि इति दृढतया प्रतिपादयति। तथापि दीर्घकालीन-न्यायविवादस्य समापनाय तथा स्वव्यापारस्य निर्विघ्न-विकासाय समाधानस्य मार्गः स्वीकृतः। अयं प्रस्तावः तदैव अन्तिमरूपं धारयिष्यति यदा ९५ प्रतिशताधिकाः वादिनः तस्य अनुमोदनं करिष्यन्ति। उल्लेखनीयम् अस्ति यत् एतस्मात् पूर्वं समवायेन दिवालियत्व-प्रक्रियायाः माध्यमेन एतानि प्रकरणानि समाप्तं त्रिवारं प्रयत्नः कृतः, किन्तु अमेरिकीय-न्यायालयैः तेषां प्रस्तावाः अस्वीकृताः। उपभोक्तृसुरक्षा, वैज्ञानिक-प्रामाणिकता, न्यायव्यवस्थायाः पारदर्शिता च उत्तरदायी-उद्योगसंस्कृतेः मूलाधाराः सन्ति। एषः प्रसङ्गः स्पष्टं बोधयति यत् जनविश्वासस्य संरक्षणमेव कस्यापि वैश्विक-समवायस्य सर्वोच्चं दायित्वम् अस्ति।

शिक्षाव्ययस्य वर्धमानो भारः : समाधानस्यान्वेषणम्

निज-आङ्गलमाध्यम-विद्यालयानां वर्धमानानि शुल्कानि परिवर्तमाना च शिक्षाव्यवस्था

प्यूपिल्स टाइम्स/शिक्षाव्यवस्था
अस्मिन् देशे निज-आङ्गलमाध्यम-विद्यालयानां संख्या यथा वर्धते, तथैव तेषां शुल्कमपि प्रतिवर्षं वर्धमानम् अस्ति। कतिपयैः राज्यसरकारैः शुल्कवृद्धेः नियमनाय प्रयत्नाः कृताः, किन्तु न्यायालयैः स्पर्ष्टीकृतं यत् यत्र विधौ पूर्वानुमतेः प्रावधानं नास्ति, तत्र शिक्षाविभागस्य केवलं सूचना एव पर्याप्ता भवति। इयं विडम्बना यत् प्रतिष्ठितविद्यालयेषु प्रवेशकाले बहवः पालकाः उच्चशुल्कं विविधान् अतिरिक्तव्ययान् च सहर्षम् अङ्गीकुर्वन्ति; प्रवेशानन्तरं तु तदेव शुल्कं गुरुभाररूपेण अनुभूयते। अपरतः आधुनिकभवनानि, आधुनिकशिक्षणकक्षाः, विज्ञानप्रयोगशालाः, क्रीडासुविधाः, परिवहनव्यवस्था, दक्षोपाध्यायाश्च इत्यादीनां व्यवस्थापनाय विद्यालयैः महदर्थनिवेशः



करणीयः भवति। सम्प्रति शिक्षा शनैः शनैः सेवारूपात् वाणिज्यरूपं धारयति। प्रतिष्ठास्पर्धया विद्यालयाः शुल्कं वर्धयन्ति, पालकाश्च स्वसन्ततीनां विद्यालयपरिवर्तनं कर्तुम् अनिच्छवः भवन्ति। अतः शुल्कनियन्त्रणं कठिनतरं भवति। शासकीयविद्यालयानां गुणवत्तावर्धनम्, शुल्कनिर्धारणे पारदर्शिता, उत्तरदायिनी नियमनव्यवस्था च अत्यावश्यकाः सन्ति।

अधुना शिक्षायाः व्ययः केवलं विद्यालयशुल्के न सीमितः। प्रशिक्षणकेन्द्राणि, पुस्तकानि, परिवहनव्ययः, अङ्गीयसाधनानि, प्रतियोगिता परीक्षाप्रशिक्षणं तथा पाठ्येतरक्रियाः अपि परिवाराणां वित्तीयभारं वर्धयन्ति। अतः शिक्षायाः वास्तविकव्ययस्य समग्रदृष्ट्या मूल्याङ्कनम् अपेक्षितम्। गुणवत्तायुक्ता, सुलभा, पारदर्शिनी, उत्तरदायिनी च शिक्षाव्यवस्था एव एतस्याः समस्यायाः चिरस्थायिसमाधानं प्रदातुं समर्था भविष्यति।



Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

प्यूपिल्स टाइम्स/संस्कृत-नाट्यम्
पात्राणि— आर्या, मञ्जरी, आदित्यः, विवेकः, किम्, सूत्रधारः।

दृश्यम्-१ : अप्रत्याशितम् आगमनम् (आचार्याः गृहद्वारे घण्टाध्वनिः। आर्या द्वारम् उद्घाटयति।) आर्या-कः भवति? आदित्यः—

आदित्यस्य रहस्यम्

अहम् आदित्यः। किं मां न प्रत्यभिजानासि? वयं बाल्ये परस्परं परिचितौ आस्ताम्। आर्या- (विस्मयेन) अहो! आदित्य! बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। कथम् अत्र आगतः? आदित्यः- भवत्याः सामाजिकजाले प्रकाशितानि चित्राणि दृष्ट्वा आगतः। विदेशवासिनः कृते स्वजनस्नेहस्य महत्त्वम् अधिकमेव अनुभूयते। आर्या- तर्हि प्रविश। अतिथिः खलु देवतुल्यः। (मञ्जरी प्रविशति।) मञ्जरी-आर्ये! कः अयम्? आर्या-एषः आदित्यः, मम पुरातनः सखा। मञ्जरी- भवतः हार्दिकं स्वागतम्। आदित्यः- युवयोः स्नेहः एव मम परमं सौभाग्यम्। **दृश्यम्-२** : मैत्र्याः प्रस्फुटनम् (कतिपयदिनानन्तरम्। सर्वे सह उपविशन्ति।) आदित्यः-कार्यव्यग्रता जीवनस्य सर्वस्वं नास्ति। हास्यं, विश्रान्तिः, मैत्री च जीवनस्य प्राणाः सन्ति। मञ्जरी-भवतः आगमनेन अस्माकं गृहे पुनः प्रफुल्लता समजायत। आर्या-अद्य बहुकालानन्तरं निश्चिन्ततया

अहसम्। आदित्यः-जीवने कदाचित् नियमेभ्यः अपि विश्रामः आवश्यकः भवति। मञ्जरी- सत्यमेव। भवतः गमनानन्तरम् इदं गृहं पुनः शून्यमिव भविष्यति। (सर्वे सह हसन्ति।) **दृश्यम्-३** : संशयस्य उदयः (क्लबे। विवेकः आर्या मिलति।) विवेकः-आर्ये! किं त्वम् आदित्यं सम्यग् जानासि? आर्या-आम्। सः मम बाल्यसखा इति मन्ये। विवेकः-मम ज्ञाने तु तत् सर्वथा सत्यं नास्ति। तस्य जीवने बहवः संघर्षाः अभवन्। सः कदाचित् असत्यमपि वदति। आर्या-एतत् श्रुत्वा मम मनः विचलितम्। विवेकः-विश्वासः करणीयः, किन्तु विवेकः अपि न परित्याज्यः। (आर्या चिन्तामग्ना निर्गच्छति।) **दृश्यम्-४** : अन्तर्द्वन्द्वम् (रात्रौ। आर्या-मञ्जर्योः संवादः।) आर्या-मञ्जरी! अद्य विवेकेन आदित्यस्य विषये विचित्राणि कथितानि। मञ्जरी-किं सः कदापि अस्मान् प्रति दुराचारम् अकरोत्? आर्या-न कदापि।

एकस्य मिथ्यावचनस्य पृष्ठे निहितं मैत्रीसत्यम्

मञ्जरी-किं धनं याचितवान्? आर्या-न। मञ्जरी-तर्हि केवलं परश्रुतिभिः कथं मित्रं परित्यजेम? आर्या-किन्तु यदि तत् सर्वं सत्यं भवेत्? मञ्जरी-प्रत्येकस्य जीवने कश्चिदन्धकारः भवति। वर्तमानमाचरणमेव मनुष्यस्य वास्तविकः परिचयः। आर्या-भवत्याः वचनानि मम हृदयं गभीरतया स्पृशन्ति। **दृश्यम्-५** : गङ्गातटे रहस्योद्घाटनम् (प्रातःकाले गङ्गातीरे। आर्या आदित्यश्च एकान्ते उपविशतः।) आदित्यः-आर्ये! अद्य मया एकं रहस्यं निवेदनीयम्। आर्या-निःशङ्कं कथय। आदित्यः-वयं कदापि सहाध्यायिनौ नास्व। आर्या-(स्तब्धा) किमेतत्? आदित्यः-एतदेव मम जीवनस्य एकमात्रं मिथ्यावचनम्। अहं सामाजिकजाले भवत्याः जीवनचित्राणि दृष्ट्वान्। तेषु शान्तिः, स्नेहः, सौहार्दं च दृष्टम्। तदेव माम् भवत्याः समीपम् आनयत्। आर्या-तर्हि अस्माकं मैत्री? आदित्यः-सा तु सर्वथा

सत्या आसीत्। न मम कश्चित् स्वार्थः, केवलम् आत्मीयतायाः अन्वेषणम्। (आचार्याः नेत्रयोः अश्रूणि, मुखे मन्दस्मितम्।) **दृश्यम्-६** : मैत्रीविजयः (सर्वे एकत्र समुपविशन्ति। किम् अपि प्रविशति।) किम्-सत्यं विश्वासेनैव शोभते। विवेकः-अद्य मम भ्रान्तिरपि निवृत्ता। मनुष्यः केवलं भूतकालेन न परीक्ष्यते। मञ्जरी-निष्कपटहृदयमेव श्रेष्ठं प्रमाणम्। आर्या- आदित्य! त्वया एकं मिथ्यावचनम् उक्तम्; किन्तु तस्मात् महत्तरं सत्यं प्रकाशितम्- यथार्था मैत्री न रक्तसम्बन्धेन, अपितु हृदयसम्बन्धेन भवति। आदित्यः-मैत्री विश्वासस्य आधारः, न तु केवलं परिचयस्य। सूत्रधारः-यः स्वार्थं परित्यज्य प्रेम, विश्वासं, सहानुभूतिं च धारयति, स एव यथार्थः मित्रम्। मनुष्यस्य मूल्यं तस्य भूतकालेन न, अपितु वर्तमानाचरणेन एव निर्णीयते। एष एव अस्य नाटकस्य सन्देशः। इति "आदित्यस्य रहस्यम्" नाम नाटकं समाप्तम्।

Defense Minister Rajnath Singh unveils two major policy reforms for the Indian Coast Guard



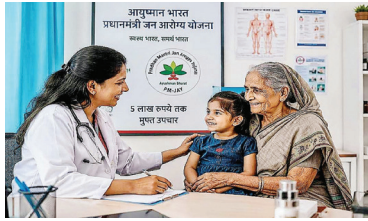
New Delhi: Defense Minister Rajnath Singh has unveiled two important policy reforms for the Indian Coast Guard (ICG). These are intended to promote gender equality in recruitment and service conditions of officers and to streamline the administrative procedures for providing ex-gratia funds to the families of personnel missing at sea while on duty. The Defense Minister appreciated the exceptional service of the ICG over the last five decades and expressed confidence that these visionary policies will further strengthen the morale and operational capability of the force as it moves towards its golden jubilee in 2027. He reaffirmed the resolve

of the Prime Minister Modi-led government to strengthen the ICG as a modern, capable and future-ready maritime force. The first policy direction establishes a comprehensive, women-centric approach by implementing a gender-neutral framework for the recruitment of officers in the ICG. Key features of the policy include inclusion of women candidates in Short Term Service Appointments (SSA) and Permanent Appointments (PA) at par with their male counterparts. The option of SSA has also been opened for male candidates. This policy ensures equal opportunities for career progression right from the initial training stage. Existing

women PA officers will also be considered for promotion to higher posts subject to fulfillment of eligibility conditions. Existing women officers serving on SSA will also be provided the option to convert their service into PA subject to fulfillment of prescribed conditions. This progressive step reflects the government's commitment towards women power and equal opportunities in the nation's maritime security ecosystem. At the same time, other policy reforms will provide relief and administrative ease to the families of those personnel who unfortunately go missing at sea in the line of duty. One of the key features of this policy is the right to 'presume dead' ICG personnel missing at sea in the line of duty for the purpose of payment of ex-gratia. This reform greatly simplifies and expedites the process of providing ex-gratia amount and final benefits to the next of kin. This measure ensures that families of martyred personnel do not have to face long administrative delays at the time of mental trauma.

Ayushman Bharat scheme implemented in the entire country

6 crore senior citizens above 70 years of age also included



New Delhi: Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) has now been implemented in all 36 states and union territories of the country. The central government has expanded the scope of the scheme to include 6 crore senior citizens aged 70 years and above. With this, the number of beneficiary families has been increased from 10.74 crore to 12 crore. Union Minister of State for Health and Family Welfare Prataprao Jadhav gave this information in a written reply in the Rajya Sabha. The minister said that initially 10.74 crore families were included under the scheme on the basis of socio-economic caste census of 2011. In view of population growth in

January 2023, it was increased to 12 crore families. After this, in March 2024, families of about 37 lakh ASHAs, Anganwadi workers and Anganwadi assistants were also included in the scheme. At the same time, it was decided to extend the benefits of the scheme to 6 crore senior citizens aged 70 years and above, regardless of their socio-economic status. Under the national portability facility of AB PM-JAY, beneficiaries can avail cashless treatment in any empaneled hospital in the country even outside their home state. This facility is proving to be very useful especially for migrant workers and people needing treatment while travelling. Till June 30, 2026, 29.05 lakh inter-state hospital admissions have been authorized under the scheme. The total value of these treatments is more than Rs 8,383.97 crore, which shows the effectiveness of the national portability mechanism of the scheme.

Big decision of Tamil Nadu government Chicken biryani will be available in mid-day meal of schools



Chennai: Now children will get chicken biryani in the mid-day meal in the schools of Tamil Nadu, this decision has been taken by the Vijay government. According to reports, the Tamil Nadu government is seriously considering the proposal to serve chicken biryani to students in the mid-day meal of primary schools once a week. School Education Minister A. Rajmohan said a formal

proposal in this regard has been sent to Chief Minister C. Joseph Vijay and he is currently reviewing it. The minister said the Justice Party started the food, Kamaraj made it a mid-day meal, Kalamazhar included eggs, then Amma added eggs every week. Now is the time for us to do better. I have proposed why not serve chicken biryani once a week. This proposal has come on the demand of teachers unions. The government aims to make the menu more nutritious and tasty. Currently around Rs 15 is spent per student, which includes poha, veet and rava upma. These will be replaced with better alternatives.

Supreme Court's suggestion 'Centre should consider strengthening disabled-friendly rules'

New Delhi: The Supreme Court has asked the Centre to seriously consider the suggestions of experts and petitioners with the aim of making improvements towards making the movement of persons with disabilities accessible and simple. So that concrete rules can be made without loopholes to ensure easy access to public places and services for such people. A bench of Justices JB Pardiwala and KV Vishwanathan took cognizance of the submissions on the framing of the rules and asked Additional Solicitor General Aishwarya Bhati, appearing for the Centre, to consider the suggestions of experts and petitioners before notifying the draft rules in the Gazette, so that they can be made more robust, error-free and implementable.



The bench said, 'Counsel for the petitioner submitted that their suggestions should be considered before finalizing the draft rules and publishing them in the official gazette, so that no loophole or lacuna remains and it would make the provisions of the (RPWD) Act more effective in achieving the purpose of the law.' The apex court also took serious note of the fact that eleven states and union territories, including Delhi, Haryana, Rajasthan, Himachal,

Karnataka, Andaman-Nicobar and Tamil Nadu, have not appointed State Commissioners to monitor the rehabilitation of persons with disabilities under the RPWD Act. The bench said that any lapse would be viewed seriously. Therefore, all the states were directed to appoint State Commissioners within four weeks under Section 79 of the RPWD Act. This instruction will be strictly followed and no state can show any laxity. The bench also directed the Centre to appoint two commissioners within four weeks to assist the Chief Commissioner under the law, so as to ensure rehabilitation of persons with disabilities. The bench has now scheduled the hearing of the PIL filed by Rajeev Raturi in January next year in 2025.

Madhya Pradesh government agreed

Farmers' agitation which has been going on for two days in Bhopal ends

Bhopal: The agitation going on in Bhopal for the last two days finally ended on Wednesday (29 July 2026). Farmers were adamant in Bhopal demanding purchase of moong at support price and changing the e-token system in fertilizer distribution. In the meeting held with the Group of Ministers in the Ministry, it was agreed to purchase 60 percent produce from every eligible farmer and postpone the e-token system. Along with this, assurance was given to seriously consider other issues also. After the meeting, Agriculture Minister Adal Singh Kanshana shared the decisions taken by the government. Officials of farmer organizations discussed with



the protesting farmers. Everyone was informed about the decision to increase the quota from 25 to 60 percent, increase the last date of slot booking and purchase, postponement of fertilizer distribution through e-token system and review it. State President of Bharatiya Kisan Union (Tikait) Anil Yadav confirmed the end of the farmers' strike. At the same time, National President of Rashtriya Kisan Mazdoor Mahasangh Shivkumar

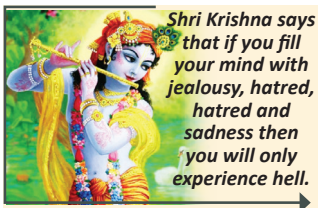
Sharma Kakka ji called it a victory for the farmers. He said that we were, are and will always be with the farmers. Here, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, while responding to the demand of Madhya Pradesh government to increase the quota of summer moong procurement, said that out of the approval given to various states for purchasing moong, maximum 87 percent has been given to Madhya Pradesh. Shivraj said in a letter to Chief Minister Mohan Yadav that a letter was received from State Agriculture Minister Adal Singh Kanshana regarding increasing the quota of moong procurement.

India will have to make a new strategy to deal with global challenges

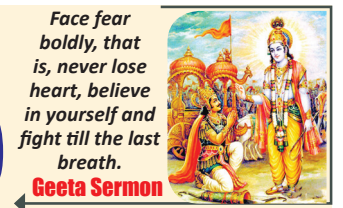
New Delhi: A report from the Finance Ministry has said that to gain strategic edge, India will have to prepare itself afresh. Not only this, we will have to rethink our ways of dealing with the changing global challenges (especially high energy prices). The report also said that it is very important to take domestic reforms and rapid policy steps to change the economic direction of the country. Pointing to the risks of increase in inflation, fiscal and current account deficit and decline in growth rate due to continued tensions in the Gulf region, the report said that rapid policy steps will have to be taken and implemented to promote foreign and domestic investment in the country's economy. Global events related to the

weaponization of AI and supply chains in general are a reminder of how far India still has to go to achieve long-term strength and strategic advantage, the July Monthly Economic Review report said. The recent years have been about facing difficulties and preparing oneself and the coming years will also be like this. The report also said that if the recent rise in global crude oil prices is sustained, it could lead to pressure on the financing of both the fiscal deficit and the current account balance. Global economic uncertainty has increased again this month due to escalating geopolitical tensions in West Asia, putting upward pressure on crude oil prices again after a period of moderation.





PUPILS TIMES



Friday, 31 July to 06 August 2026

Four years of President Murmu's tenure completed

Many new initiatives started in Rashtrapati Bhavan



New Delhi: President Draupadi Murmu inaugurated and laid the foundation stone of several new initiatives at Rashtrapati Bhavan and Rashtrapati Estate to mark the completion of four years of her tenure. During this, e-audio guide for visitors, 'Bachpan Bal Parisar' for children, 'Raahi' electric bus service, third edition of e-Uphaar and various infrastructure projects were launched. Besides, several publications based on the four-year tenure of the President were also launched.

App-based e-audio guide of Rashtrapati Bhavan launched, which will be available in Hindi, English and 14 other Indian languages. Sign language module has also been included in it, which will also provide convenience to disabled visitors. 300 selected gifts received by the President have been included in the third edition of e-Uphaar for public auction. This auction will be held from August 5 to September 5, 2026. 'Bachpan Bal Parisar' for children was inaugurated at the President's Estate. It includes facilities like

Play Zone, 'Kilkari' and 'Samarth Anganwadi-cum-Crib', which aim to provide a safe and conducive environment for the holistic development of children. Free electric bus service started under Rashtrapati Bhavan Access and Heritage Interconnector (RAAHI). Operated by women drivers and conductors, this service will be available to the staff of Rashtrapati Bhavan and residents of the Rashtrapati Estate and will promote safe and convenient movement of women, children, senior citizens and persons with disabilities. The President laid the foundation stone of the Service Block under the Net Zero Energy Strategy. Also inaugurated new residential facilities at Rashtrapati Niketan (Dehradun) and Rashtrapati Nilayam (Secunderabad) and also laid the foundation stone for redevelopment of staff quarters at the Rashtrapati Estate. President Murmu said that it has been his endeavor that Rashtrapati Bhavan remains a living symbol of India's rich traditions, democratic values and national ideals.

PM Modi holds second high-level meeting with secretaries

Discussion on the goal Of developed IndiaNew

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with Central Government Secretaries at his residence 7, Lok Kalyan Marg. In the meeting, the future action plans of ministries and departments related to finance and economy, commerce and industry and technology were reviewed. During this period, special emphasis was laid on better coordination between ministries, technical self-reliance, people-centric good governance and innovation-based governance to accelerate the goal of a developed India. The Prime Minister stressed the need to develop a strong team spirit among ministries and departments and called upon officials to work with a common objective. He said that better coordination and effective results should be ensured by eliminating both horizontal and vertical functional barriers within the government. PM Modi said that the citizens of India should always be at the center of the governance system. He said that every decision and policy of the government should be made keeping in mind the interests and aspirations of the common citizens. The Prime Minister



said that while India is investing extensively in infrastructure, equal priority should be given to development of indigenous technologies and domestic capabilities. He described technological self-reliance in important sectors as essential for the economic progress and strategic strength of the country. On energy security, he said that it is directly related to national security, economic stability and welfare of citizens. He called for enhancing self-reliance in the energy sector through innovation, diversification and capacity building. The Prime Minister said that reforms should not be seen as just a trend, but as an ongoing need for effective governance. He stressed on improving procedures, improving work

culture and strengthening institutional efficiency. Referring to the increasing use of digital technologies, PM Modi stressed the need to strengthen cyber security. He said that it is important to protect digital systems and infrastructure from emerging cyber threats. Also called for connecting young innovators and entrepreneurs with the cyber security ecosystem and giving it the form of a people's movement. The Prime Minister said that in strategic areas where India is growing rapidly, the government should maintain active public relations and effective communication. He stressed on countering misinformation and unfounded apprehensions through effective communication in a timely manner. PM Modi said that new educational courses should be developed in collaboration with the industry to provide skills to the youth as per the needs of emerging and future industries. He said that the government must always remain young, dynamic and visionary and must constantly adapt itself with agility and innovation to new challenges and opportunities.

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)

Recover Faster, Heal Better, Get Back to Life Sooner



Dr. Arvind Singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

ERAS is a modern, evidence-based approach that helps patients recover faster after surgery while reducing pain, complications, and the length of hospital stay. Instead of focusing only on the operation, ERAS improves every stage of surgical care from preparation before surgery to recovery afterwards.

Surgery is only half the battle. The real victory is how quickly and safely you return to your normal life. That is exactly what Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) aims to achieve.

The program combines better nutrition, advanced anesthesia, effective pain control, early eating, and getting patients out of bed and walking as soon as it is safe. These simple but scientifically proven steps help reduce surgical stress, preserve muscle strength, lower the risk of complications, and speed up recovery.

Today, ERAS is successfully used in colorectal, gastrointestinal, gynecological, urological, orthopedic, and many cancer surgeries. Studies from around the world have consistently shown that patients following ERAS protocols recover sooner, experience fewer complications, and return to their daily activities more quickly.



ERAS is not a new operation or a new medicine. It is a team effort involving surgeons, anesthesiologists, nurses, physiotherapists, dietitians, and, most importantly, the patient. Following medical advice, staying active, and maintaining proper nutrition are essential parts of the recovery process.

Modern surgery is no longer judged only by a successful operation, but by how well and how quickly patients regain their health and independence. ERAS is transforming surgical care by making recovery safer, smoother, and more comfortable than ever before.

Planning for surgery? Ask your surgeon whether an ERAS program is right for you. A faster recovery often begins even before the operation.

PUPILS TIMES

Core Committee

Shivprakash Pandey Chief Publisher

Vikas Maurya Co Publisher

Address : Shop No.3, Khatri NX Apt.,
Valivali, Badlapur (West) - 421503.

Web : pupilstimes.com



LIFE INSURANCE CORPORATION
OF INDIA

"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:

- ✓ Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- ✓ New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- ✓ Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- ✓ Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- ✓ Also Available — Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:

- ✓ Life Insurance + Savings Plan
- ✓ Child Education and Marriage Planning
- ✓ Retirement Planning
- ✓ Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"

FREE POLICY
CONSULTATION



LIC Agent
Archana Shukla

☎ +91 91129 39085

☎ +91 74998 67628

Shop No. 2, Near Vithal Mandir,
New Vadavali Chowk,
Badlapur (West) - 421503

LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printed, Published & Owned by : ANIL MISRA, Printed at SOMANI PRINTING PRESS, UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. Published at : 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, article and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - ANIL MISRA, Mob. : 92208 68564, Email : anilmisrapc@gmail.com. PRGI. No. : MHMUL/25/A2419